खंड: 7, अंक: 2 फरवरी 2024 RNI- DELHIN/2021/84711
ISSN- 2584-2803 (Print)

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

विकसित भारत @ 2047: संभावनाएं एवं चुनौतियां

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस
वैश्विक अध्ययन केंद्र
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)
दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

विकासशील राज्य शोध केंद्र (डीसीआरसी), एआरसी बिल्डिंग, गुरू तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-**110007** की ओर से सुनील कुमार द्वारा प्रकाषित एवं सी के प्रिटिंग प्रेस, 5-ए/177-178, गली न० 7, डब्ल्यू, करोल बाग नई दिल्ली-**110005** द्वारा मुद्रित तथा विकासशील राज्य शोध केंद्र प्रकाशित (डीसीआरसी), एआरसी बिल्डिंग, गुरू तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-**110007** से प्रकाशन, संपादक सुनील कुमार

© डीसीआरसी2024

संश्लेषण

विकसित भारत @ 2047: संभावनाएं एवं चुनौतियां

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. विकसित भारत की बात — डॉ. अभिषेक नाथ 1–7
2. विकसित भारत @ 2047: चुनौतियाँ और समाधान — प्रोफेसर (डॉ) अर्चना सौशिल्या 8–14
3. विकसित भारत का अर्थ — नविता कुमारी 15–18
4. विकसित भारत @ 2047: एक अध्ययन — हिताक्षी गिल 17–23
5. विकसित भारत@ 2047: सर्वांगीण विकास — डॉ. जूही सिंह और डॉ. बबीता वर्मा 24–32
6. भारत की दिशा–निर्देश : 2047 में एक उदार व विकसित राष्ट्र — उषा बाल्मीकि 33–39
7. विकसित भारत के समक्ष चुनौतिया: बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में एक अध्ययन — चंद्रिका आर्य 40–44

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 69वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधाथियों, शिक्षाथियों एवं विद्याथियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत ने एक वृहत, विविध एवं व्यापक लोकतांत्रिक यात्रा पूर्ण करने का प्रयास किया है। शीत युद्ध में विभक्त संपूर्ण विश्व जब अमेरिका व सोवियत संघ के सैन्य गुटों में संघर्षरत था, तब भारत ने गुटनिरपेक्षता के रुप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया। विकासशील राष्ट्रों को एक नव विश्व की श्रेणी में लामबंत करने में भारत ने एक अग्रणीय भूमिका निभाई। प्रतिकूल परिस्थितियों के पश्चात भी अपने 75 वर्षों की लोकतांत्रिक राजनीति में भारत वश्विक दक्षिण राज्यों के अग्रदूत के रुप में क्रियाशील रहा है।

75 वर्षों की अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में एक राष्ट्र राज्य के रुप में भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र से एक उभरती वैश्विक राष्ट्र शक्ति के रुप में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। गत दस वर्षों में 21वीं शताब्दी का नया भारत एक नव राष्ट्र राज्य के रुप में न केवल विश्व की पांचवी आर्थिक शक्ति के रुप में उभरा है बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी एक विकसित राष्ट्र की ओर निरंतर कार्यरत हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिणित करने का संकल्प लिया है।

वर्ष 2047 में जहां भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वष पूर्ण करेगा वहीं वह पश्चिमी देशों के समकक्ष एक विकसित राष्ट्र राज्य के रुप में भी स्वयं को संकल्पित एवं सशक्त कर सकेगा। विकसित भारत की यह यात्रा अनेक सरोकारों एवं चुनौतियों से परिपूर्ण होगी। राजनीतिक स्थात्विय,

सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक समावेशिता तथा आर्थिक गुणवत्ता भारत की इस यात्रा के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगी।

वैश्विक स्तर पर विषय की महत्ता तथा राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'विकसित भारत@2047: संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर लेख आमंत्रित किये। सात उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 31 मार्च 2024

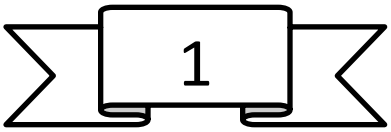

विकसित भारत की बात

डॉ. अभिषेक नाथ

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. कॉलेज, सहरसा

एक राष्ट्र और राष्ट्रवासी के लिए इससे बेहतर बात नहीँ हो सकती कि उसका राष्ट्र अपने पिछड़ेपन को दूर कर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होद्य जाहिर है हर भारतीय यह चाहेगा कि उसका देश एक विकसित देश बने, लेकिन कोरी कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच सबसे महत्वपर्ण आयाम है प्रयास का। और शायद ही कोई इस बात से इंकार करेगा कि हर भारतीय अपना सर्वोतम योगदान दे ताकि विकसित का तमगा हासिल किया जायेद्य वर्तमान भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री की यह उद्घोषणा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है एक ऐसा ही प्रयास साबित हो सकता है यदि यह केवल विचारधारात्मक लामबंदी न हो तो|

यह आलेख विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ आधारभूत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का प्रयास है तथा वास्तविकता और विचारधारात्मक मॉडल के बीच के फासले को विश्लेषित करने का प्रयास करता है।

भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के कयासों की यह पहली उदघोषणा नहीं है। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में यह चर्चा जोर–शोर से थी कि अगली सदी एशिया की होगी जिसमें भारत और चीन दो महत्वपूर्ण सहयोगी–प्रतियोगी होंगे। भारत के लिए ऐसी ही संभावनाओं की चर्चा 'भारत 2020' नामक किताब में महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं और इसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विजन और प्रयासों को इंगित करता है। लेकिन भारतीय सत्ता के गलियारों में जहाँ सत्ता का विजन देश और समाज के विजन से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता रहा है उनकी इस चर्चा को कभी भी एक गंभीर सोच के रूप में नहीं लिया गयाद्य वावजूद इसके कि यह सर्वविदित था कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं वाला राष्ट्र होगा। और यदि इस लाभ का भारत ने इस्तेमाल

नहीं किया तो शायद विकसित राष्ट्र बनने का भारत का सपना और प्रयास दोनों ही भविष्य में अपर्याप्त साबित होंगे।

'विकसित भारत' का विषय एक विशद चर्चा का विषय है किन्तू इस आलेख की शब्द सीमा को देखते हुए यह लेख अपनी चर्चा कुछ सीमित आर्थिक मापदंडों और विचारधारात्मक, इन दो बिन्दुओं पर केद्रित करने का प्रयास करेगा।

अर्थव्यवस्था की बात

कभी यह काफी चर्चा का विषय था कि 'भारत अमीर देश है लेकिन भारतीय गरीब है' (रंजनरू 2022)। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यावस्था है जो 3 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी जीडीपी वाला देश है और शीघ्र ही हम 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। अर्थात भारत की अमीरी बढ़ेगी लेकिन क्या भारतीओं की गरीबी कम होगी? क्या 1.4 बिलियन जनसँख्या के लिए यह प्रयाप्त है? तुलना में 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग साढ़े पांच गुणी जायदा लगभग 19 ट्रिलियन थी और जनसँख्या लगभग समान। बावजूद इसके कि पिछले कछ समय से भारत की जीडीपी विकास दर 6ः से अधिक रही है, दो अंकों की विकास दर अभी भी चुनौती है और जनसँख्या के आकार को देखते हुए प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2200 डॉलर है, जबकि मलेशिया जैसी घनी आबादी वाले देश में भी यह 10000 डॉलर से ज्यादा है। भारत के विकसित कहे जाने वाले राज्य भी (कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडू) 3000 डॉलर तक पहुँच पाए है। इस सन्दर्भ में 2021 में भारत दुनिया के 193 देशों में 145वे स्थान पर थाद्य क्रय शक्ति समानता (परचेजिंग पॉवर पैरिटी), जो देश की आय के साम्यपूर्ण वितरण को प्रदर्शित करता है, भारत 193 देशों में 128वे स्थान (2021) पर था। जो यह अभिव्यक्त करता है कि क्यों भारत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। जैसा कि जॉन राल्स(1971) ने भी लिखा है कि हम कुछ संपन्न लोगों की सम्पन्नता को बढाकर अधिकतम शुभ को तो बढा सकते है लेकिन वह अधिकतम लोगों के शुभ को बढ़ने वाला साबित नहीं होगा।

यद्यपि रोस्टो (1960) और माल्थस (1798) जैसे अर्थशास्त्रियों के ग्रोथ मॉडल को आज ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता जो कि क्रमशः कृषि अर्थव्यवस्था (पारंपरिक समाज) से जनपुंज उपभोग की अवस्था में लगने वाले समय तथा जनसँख्या और अर्थव्यवस्था के संबंधों को विश्लेषित करते है। अगर इस गणित के विश्लेषण में हम ना भी पड़े तो कम से कम इतना तो कह ही सकते है कि भारत की युवा शक्ति का सर्वोत्तम इस्तेमाल उनकी शिक्षा के स्तर, उनके स्वास्थ, भोजन की

उपलब्धता और रोजगार पर निर्भर करता है। शिक्षा पर कई आयोगों के सुझावों के बावजूद हम अभी भी जीडीपी का 3ः तक ही निवेश कर सके है। NEP 2020 इसे 6ः तक करने के लक्ष्य को पुनः दोहराता है। एक सर्वे के मुताबिक 80ः भारतीय इंजीनियर नौकरी के लिए आवश्यक कौशल नहीं रखते। कृषि के हालत भारत जैसे विशाल कृषि क्षेत्र वाले देश की भी वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देशों में 111वें पायदान (2023) पर होने, जो कि 'गंभीर भूख की स्थिति' है, भारतीय कृषि की दशा को बयां करता है। आर्थिक राष्ट्रवाद की पहली माँग है खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, जिसे वर्तमान में हम पोषक भोजन की उपलब्धता और उस तक नागरिकों की पहुँच से भी जोड़े तो गलत नहीं होगा। आखिर युवाशक्ति की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना स्वस्थ है?

1990 के दशक से नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत चाहे वह मजबूरी बस ही रही है, लगभग तीन दशकों के बाद भी गाँव तक तो दूर अभी मध्य श्रेणी के शहरों तक ही अपना लाभ दिखा पाई है। शिक्षा और स्वास्थ दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर सक्रिय है। लेकिन प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों ही अधिकांश भारतीयों की आर्थिक पहुँच से बाहर है। जहाँ प्राथमिक स्तर पर सरकारी व्यवस्था का यह हाल है कि गरीब से गरीब भी अगर थोडा बेहतर कमाता है तो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजना चाहता है। वही दूसरी तरफ उच्च शिक्षा निजी क्षेत्रों में इतनी महँगी है और गुणवता में कमतर है कि लोग सरकारी विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं। जबकि यदि स्कूल के स्तर पर यदि सभी को और एक समान शिक्षा का प्रावधान हो तो नागरिकों में अंतर को भरा जा सकता है और फिर वह युवा के रूप में कर्ज लेकर भी अपनी क्षमता के बल पर गुणवतापूर्ण शिक्षा ले सकता है और अर्थव्यवस्था में योगदन कर सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का निजी संचालन इस दशा में पहूँच गया है कि लोग सरकारी अस्पतालों को भीड़ के बावजूद प्राथमिकता देते है। कोरोना कल में सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व को स्थापित कियाद्य शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले है।

कौशल की कमी बेहतर रोजगार अवसरों की कमी के साथ मिलकर इसे और भयावह बना देते है। जिसके कारण मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप और मुद्रा लोन जैसे कई आकर्षक कार्यक्रमों के बावजूद भारत में नवाचार और कौशलपूर्ण श्रमबल की कमी जनसँख्या को बड़ी बोझ में तब्दील कर सकती है। भारत में अभी 65ः जनसँख्या 35 साल से कम की है जो अगले 15 बर्षों

में युवा से वृद्ध की तरफ आग्रसर होगी और अर्थव्यवस्था पर बोझ को बढ़ाएगी। भारत में कृषि के बाद सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमबल लगा हुआ हैद्य कृषि के श्रमबल को रोजगारपरक बनने के लिए उत्पादन क्षेत्र में रोजगार बढाने की आवश्यकता है जिसके बिना विकास आगे नहीं बढेगा। चाहे चीन हो या दक्षिण कोरिया उनके तेजी से विकास का एक बड़ा कारण उत्पादन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार रहा है दक्षिण कोरिया इसलिए भी तुलना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत (1947) और दक्षिण कोरिया (1948) एक साथ आजाद हुआद्य आज विश्व में दक्षिण कोरिया की कई बड़ी कम्पनियाँ देखी जा सकती है जैसे कि एलजी, सैमसंग, हुंडई, किआ आदि महत्वपूर्ण है जबकि भारत की आज भी टाटा और हाल में भारती को छोड़कर अन्य कोई कंपनी दुनिया में अपनी साख स्थापित नहीं कर पाई है।

विकसित भारत के लिए अर्थव्यवस्था के ये आयाम अति महत्वपूर्ण हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आशा है कि वर्तमान सरकार की गतिविधियाँ और नीतियाँ इसे सही पटरी पर लायेंगी।

विचारधारा की बात

एंड्रू हेय्वूड (2002) ने लिखा है कि विचारधाराएँ अपने को स्थापित करने के लिए जनमानस को एक सुनहरे भविष्य का मॉडल प्रस्तुत करती है और उसे प्राप्त करने के लिए अपने पीछे चलने की वकालत करती है। यदयपि मार्क्स ने अपने विचारों को एक वाद (विचारधारा) मानने से इंकार किया लेकिन साम्यवाद की कल्पना करते हुए उसने कहा कि यह एक ऐसा समाज होगा जिसमे हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान करेगा और उसे उसकी जरुरत के हिसाब से दिया जाएगा। जिसके द्वारा एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। लेकिन मार्क्स ने कभी भी ऐसे समाज का कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि यह कैसे स्थापित होगाद्य आज इस विचार की अभिव्यक्ति के 175 वर्षों बाद भी कही भी ऐसा राज्य स्थापित नहीं हो सका है।

भारत ने अपनी आजादी के साथ नेहरु की 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' और 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' के मॉडल को प्रस्तुत कियाद्य जिसमे उदारवादी और समाजवादी दोनों ही मॉडलों के गुणों को समाहित कर एक नए समाज और राष्ट्र के निर्माण की कल्पना थी। जो वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बाद इंदिरा गाँधी ने 'समाजवाद और गरीबी हटाओ' के विचार को प्रस्तुत किया। 1990 के दशक तक इन सभी विचारों की वस्तुस्थिति जनता के सामने थीद्य सभी के पीछे जनमानस खड़ा हुआ और फिर खुद को ठगा हुआ महसूस किया। आश्चर्य नहीं है कि हर बदलती पीढ़ी, जो

लगभग 20–25 बर्षों में होता है, का अपने शासकों और उनकी वैचारिकी से उनका मोहभंग हुआ। 1990 के दशक में नवउदारवादी व्यवस्था ने इस विचार को आगे बढाया कि 'विकास की बाढ़' आएगी जिसमे सभी क्षेत्रों और समुदायों को विकास का पूरा मौका मिलेगाद्य लगभग एक पीढ़ी बीत जाने के बाद विकास की असामनता ने जनमानस को इस विचार के छलावे को भी स्पष्ट कर दिया है और आश्चर्य नहीं कि 2015 के आम चुनावों में एक नयी पीढ़ी ने न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर नव–रुढ़िवादी विचारों के पीछे लामबंदी दिखाई। USA में डोनाल्ड ट्रम्प की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' और भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 'अच्छे दिन आने वाले है' का विचार ने जनता की लामबंदी की वैचारिकी को तैयार किया।

भारतीयों की गारंटीः

भारतीयों ने हमेशा ही अपने शासकों को अपने समर्थन की गारंटी दी है जिनमे उन्हें आशा की किरण दिखाई देती है। किन्तु पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज और खासकर उच्च राजनितिक–आर्थिक स्तर की स्थिति ने इस समझ को बल दिया है कि 'भारत एक बेईमान समाज के रूप में उभरा है, जहाँ बेईमानी एक प्रमुख नीति बन गई है और समाज में बेईमान लोगों की सफलता ईमानदारों की तुलना में गुणात्मक रही है'। इस समझ ने ईमानदार लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि उनकी ईमानदारी किस कम की जब समाज में उन्नति का यह आधार ही नहों है। इस बात को नकारना मुश्किल है कि आज भारत में अगर राजनीतिक–प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो ईमानदार लोगों की सूची बनानी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साल दर साल की रिपोर्ट में भारत भ्रष्ट देशों की सूची में अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाया हैद्य उपरोक्त सूची में भारत वर्ष 2003 में 83वें, 2010 में 91वें, 2020 में 86वें, 2023 में 93वें स्थान पर है।

भारत में नवउदारवादी व्यवस्था में खासकर बढ़ते भ्रष्टाचार, घोटालों, क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण इसके विरुद्ध उभरे 'अन्ना आन्दोलन' में भारत ही नहीं विश्व स्तर से भारतीयों का इसको समर्थन एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन इसी आन्दोलन से जन्मी एक पार्टी आज खुद भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरी है और इसके कई नेता जेल में है। आज भारत के शायद ही किसी राज्य में या केंद्र स्तर पर एक सशक्त लोकपाल की स्थापना, जो इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी, हो पाई है। वर्तमान सरकार की 2014 में सफलता के पीछे भारतीओं की यही गारंटी थी कि हमें साफ सुथरी नेतृत्व चाहिए और इस अर्थ में वर्तमान सरकार में काफी हद तक अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। काले धन को खत्म करने के प्रयासों, विमुद्रीकरण जैसे प्रयासों को काफी परेशानी उठाकर भी भारतीयों ने समर्थन दिया। हालाँकि यह लेख वर्तमान सरकार का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देना

चाहता और इसे भारतीओं की समझ और गारंटी पर छोड़ना उचित समझता है कि वे खुद ही अपने 'अच्छे दिनों' का मूल्यांकन करें।

मन की बातः

जहाँ तक विकसित भारत की बात है आर्थिक आंकड़े और विश्लेषण भारत और भारतीयों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को उजागर करते हैद्य अतरू यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कही 'अच्छे दिन आने वाले है' से लेकर 'विकसित भारत 2047' की बात केवल विचारधारात्मक स्तर पर भारतीय जनमानस की लामबंदी तक ही सीमित नहीं रह जाए। हालाँकि वर्तमान सरकार की सशक्त नीतियाँ, मुश्किल निर्णय लेने की क्षमता और उन्हें लागु करने की इच्छाशक्ति को देखते हुए इस बात को काफी हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि नीतिओं में निरंतरता और उनका अनुपालन विकसित भारत के पथ को प्रदर्शित कर सकता है। अगर युवा शक्ति का इस्तेमाल विचारधारात्मक लामबंदी से ज्यादा विकासात्मक लामबंदी के लिए हो तो निश्चय ही विकसित भारत के स्वप्न को यह सरकार साकार कर सकती है। भारतीयों का वर्तमान सरकार पर काफी भरोसा भी है और आशा है कि विचारधारा और वास्तविकता के अंतर को यह सरकार अपने प्रयासों से पूरा करेगी। इस लेख के लेखक के मन में हमेशा यह बात रही है कि– मेरा जन्म तो विकासशील भारत में हुआ है लेकिन मेरी मृत्यु विकसित भारत में होद्य निश्चय ही यह सभी भारतियों के भी मन की बात है।

संदर्भ सूची

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल और राजन, वाई.एस. (1998), इंडिया 2020ः अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, पेंगुइन, न्यू डेल्ही.

माल्थस, थोमोस, राबर्ट (1798), अन एस्से ओंन द प्रिंसिप्ल ऑफ पौपुलेसन, जे. जोंशन पब्लिकेशन, लन्दन.

रंजन, रमेश (2022), इंडिया इज रीच बट इंडियन्स आर पुअर, लिंक्डइन, 7 अक्टूबर 2022.

रोस्टो, डब्लू. डब्लू. (1960), द स्टेजज ऑफ इकनोमिक ग्रोथः अ नॉन–कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (https://www-education-gov-in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0-pdf) असेस्ड ओन 15 मार्च 2024

हेयवूड, एंड्रू (2002), पॉलिटिक्स, पाल्ग्रेव, लन्दन.

भ्रस्टाचार सूचकांक, (भारत), (https://www-transparency-org/en/countries/indi), असेस्ड ओन 15 मार्च 2024

वैश्विक भूख सूचकांक, भारत (https://www-globalhungerindeÛ-org/india-html) असेस्ड ओन 15 मार्च 2024

♦♦♦♦♦

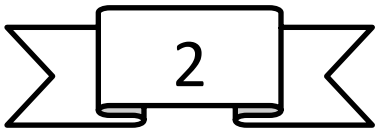

विकसित भारत @2047: चुनौतियाँ और समाधान

प्रोफेसर {डॉ} अर्चना सौशिल्या

अदिति महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विकसित शब्द का तात्पर्य भविष्य के विकास से है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो हम भारत के विकास को दर्शाते हैं, और जब भारत @२०४७ की बात करते हैं तो उसका आशय वो है जो 2047 तक हमारे देश की स्थिति को विकसित इकाई में बदल देग। उस समय भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है की इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत के चार स्तंभों की पहचान करना है जो विकास की नीवं रखेंगे– युवा, गरीब, महिलाएं और किसा। इनके माध्यमों से भारत का विकास होगा। ये चार स्तंभ भारत को एक विकसित देश के रूप में आकार देने में सक्षम होंगे।

भारत को बदलने की दृष्टि से और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अपने अंतरिम बजट 2024 में राज्य सरकार के विकास और विकास संबंधी सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। विकसित भारत रोडमैप योजनाओं में, सहायता प्रदान की जाने की बात कही है। एमएसएमई एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभर कर, अपनी वृद्धि और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं ।

11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के विविध आयामों की भूमिका पर जोर दिय। व्यक्तिगत विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका और कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा की गयी, क्योंकि किसी भी देश का विकास ,उस देश के लोगों के विकास पर निर्भर करता है। युवा पीढ़ी देश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे देश के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए विकसित भारत के राष्ट्रीय साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ,उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। युवाओं की आवाज से भारत के विकास का उद्देश्य पूरा होगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने भारत का पोर्टल लॉन्च किया है जहां युवा विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार

व्यक्त कर सकते हैं। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विभिन्न विषयों पर विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है, जिससे विकसित भारत के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने आप में एक उद्धरण बन गया है, जिसने राष्ट्रीय विकास जैसे महत्पूर्ण विषय पर लोगो के साझा दृष्टिकोण को अपने नीतियों के निर्माण में कारक बना लिया है। यह प्रयास नागरिको के सशक्तिकरण और सामूहिक जुड़ाव की अद्भुत कहानी है जिसने पुरे भारत को एक साथ जोड दिया है।

इस यात्रा का उद्देश्य, जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करना और प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति हासिल करना है। जिसका परिणाम यह निकला की आज तक जितने लोगो ने उज्जवला योजना से लाभ नहीं लिया था उनमे से, पहले ही दिन 21000 से अधिक लोगों ने पीएम उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकरण कराया। वीबीएसवाई द्वारा प्रस्तुत, कृषि क्षेत्र में विकास के एक प्रदर्शन का भरपूर लाभ किसानों ने अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया है। 120 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदर्शन आयोजित किए गए, साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ आकर्षक बातचीत भी हुई। सभी को 100ः आयुष्मान कार्ड संतृप्ति, का उद्देश्य बताया, 200 से अधिक लाभार्थियों ने मेरी कहानी, मेरी जुबानी प्रस्तुत करके लोगो के विश्वास को बढ़ाया जो उनके जीवन में सरकार की प्रमुख योजनाओं द्वारा लाए गए परिवर्तन से आया हैं। सविकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की आजादी के बाद ,अब तक की सबसे बड़ा जन आंदोलन है जो एक एक घर में पंहुचा हैं। स्वतंत्र भारत के लिए एक साथ होना तो हमारी मजबूरी थी ,ललक थी, क्योकि हम आजाद होना चाहते थे, पर यह संकल्प यात्रा उसके बाद की विकास की यात्रा है

हमारे असितत्व की पहचान हैं, हम कैसा भारत चाहते हैं। ,इसकी शुरुआत बहुत पहले हो सकती थी ,पर किसी भी प्रतिनिधि ने हमसे हमारी पस्चान नहीं पूछी, हमारी इच्छा के अनुसार भारत का निर्माण नहीं हुआ, पर अभी भी देर नहीं हुई है। यद्यपि, समावेशी विकास की चर्चा होती रही, सरकार आती जाती रहीं ,प्रयास भी होते रहें और हम विकास भी करते रहे, इनमे कोई दो मत नहीं पर आज जिस रूप में समावेशी प्रक्रिया के दृष्टिकोण को अपना कर वकास को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया गया है वह प्रशंशनीय है क्योकि सरकार अपनी हर योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो गयी है और भारत के विकास का सेहरा भी हम सबके द्वारा ,हम सबसे ही बंधवाने पर हमें ही मजबूर भी कर रही है। सभी सुविधाओं को

मुहैया करवा कर ,हमें अपने विकास के लिए बाध्य कर रही है क्योकि सबका साथ ही सबका विकास करेगा।

हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया नारा.ष्यही समय है सही समय है, भारत का अनमोल समय हैष भारत के सभी नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है,क्योकि यह उद्घोष अपने आप में पूर्णता को दर्शाता है–वक्त सही है विकास का ,प्रगति का। बहुत बड़ी संख्या में देश भर से भारतीय वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत की संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। इस अमृतकाल (1947–2047) में हमारे लक्ष्यों को साकार करने के लिए वर्ष 2047 तक भारत सरकार ने 2014 से जितने भी कल्याणकारी नीतियां शुरू कीं थी, उन सबको 2047 तक 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य लिया गया हैं ।

2014 से अब तक की उपलब्धि का सारांश आंकड़ों से देखा जा सकता है जैसे 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं जो 2014 में गरीबी रेखा से नीचे थे, एलपीजी कनेक्शन 55% (2014} से 83% हो गया है। 17% से 70% तक घरों में नल से जल आ चूका है। ये 100 प्रतिशत गारंटी योजनाएं मोदीवादी दर्शन है, जिन्होंने कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि चूंकि वह इन्हीं समुदायों में से एक हैं, इसलिए उन्हें उनके दुःख दर्द का अहसास होता है, और उनके आशीर्वाद ने उनको आज वहां खड़ा किया है की वे उनके लिए कुछ कर सके। ईश्वर उन्हें यहाँ लेकर आया है। इसलिए उन्होंने अपनी संकल्प यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म शताब्दी पर 26 जनवरी 2024 को शुरू की, हालांकि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी ,जब लगभग 1000 सरकारी अधिकारियों को सभी कल्याण कार्यक्रमों के कामकाज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए गांवों में भेजा गया था।पर विधिवत इस योजना को मोदीजी ने २०२४ में प्रारम्भ किया है.

"यही समय है सही समय है "का यह एक्शन प्रोग्राम महिला, युवाओं और श्रमिकों को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ,नयी गति प्रदान करने हेतु तत्पर है। हम 21वीं सदी में अपने लक्ष्यों को साकार करने में, किसी के द्वारा रोका नहीं जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जनवरी जैसा आंदोलन बनाया है ,आज उनकी गारंटीयुक्त गारंटी की गाड़ी को भारी समर्थन मिला है, क्योंकि यह गारंटी किसी और की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसलिए भारत की जनता इस गारंटीयुक्त मिशन में 100ः विश्वास दिखा रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ नए घर आवंटित किए गए हैं, उज्जवला योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज के लिए 5 करोड़

दिए गए, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिली,हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य 140 करोड़ जनता की क्षमता को साकार करना है। उनका यह गारंटी कार्यक्रम –विकास की गारंटी हैं यह मिशन गारंटीयुक्त कल्याण कार्यक्रम है, और इसके लिए ,सभी को मोदी जी के साथ हाथ मिलाना होगा..सबका प्रयास सबका विकास।

अगर प्रबुद्ध जन भारत के इस प्रधान मंत्री के पिछले 10 वर्षों के कामों की समीक्षा करे, तो उन्हें खुद यह अहसास होगा की प्रधानमंत्री जो बोलते हैं पहले खुद उसी में लग जाते हैं, वह खुद ही कार्रवाई पहले करते हैं, और उन्हें काम करते देख पूरा देश उनका अनुसरण करता हैं। फिर मोदी जी उन विचारो को योजना के रूप में समाज के सामने लातें हैं। लगभग सभी वर्गों से साक्षात्कार के दौरान मैंने यह महसूस किया कि अन्य प्रधानमंत्रियों के विपरीत, मोदी जी लोगों के दिमाग और आत्मा को सिर्फ एक राजनीतिक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नेता की तरह नियंत्रित करते हैं, एक कर्मठ व्यक्ति की तरह ,जिके कार्य ,शब्दों से अधिक बोलते हैं। उनके सभी लाभार्थी, कल्याणकारी नीतियों और यहां तक कि युवाओं ने भी उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में अनोखी बातें की। उनकी ऊर्जा और उनका युवापन, उन्हें गंतव्य तक पहुंचने तक न रुकने के लिए प्रोत्साहित करता है। बोर्ड और परीक्षाओं में शामिल होने वाले छोटे बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा करके जो आत्मविश्वास पाया है ,वो माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुआ है। एक प्रधानमंत्री बच्चो ,महिलाओं और गरीब से जब इतना मानवीय मूल्यों पर जुड़ जाये तो शायद वह नेता की परिधि से बाहर आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। युवा और वृद्ध उनके ऊर्जा से कायल हैं। उनकी जीवन शैली लोगो के लिए अनुकरणीय होती जा रही हैं–क्या बच्चा क्या युवा और क्या गरीब। पोर्टल पर छात्रों से फीडबैक मांगना और विकसित भारत पर उनके परामर्श को जानना ,अनेक प्रश्नों का उत्तर पाना और उनकी इच्छा जानना की 2047 में उनके अनुसार ,विभिन्न पहलुओं में विकसित भारत कैसा दिखना चाहिए,यह अपने आप में अनूठा प्रयास है, जिसे हम शिक्षक वर्ग अपने अभ्यास में करते हैं। भारत का स्वरुप हर एक भारतीय निर्धारित करेगा। इतना ही नहीं, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? और यह युवा अपनी भूमिका योगदान के बारे में उल्लेख कर के भारत निर्माण में सरकार के साथ भागीदारिता दिखाए, आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की ऐसी, पहल नहीं थी।

विकसित भारत के इन चार आयामों को स्तम्भ बना कर उन्होंने एक ऐसे संस्कृति पैदा कर दी है की,हर प्रतिनिधि– पक्ष या विपक्ष अपने कार्यो की स्वीकृति पाने हेतु जनता के विचारो और सहमति पर आश्रित हो गए है– उन्होंने ने पुरे भारत को परिवार बना दिया है– जहाँ किसान रोटी देता

है ,महिलाये पकाती है ,बच्चे उनके प्रति श्रद्धा दिखा कर संस्कार और कर्मठ बनते है और घर के दरवाजे पर आया हर गरीब नारायण बन जाता है।

ऐसे ही विचारों की समरसता ,समावेश मैंने गाँधी दर्शन में पाया है। गाँधी जी ने सर्व भाव संभव की बात कही ,अहिंसा के द्वारा मूल्यपरक नैतिक उत्थान की बात कही ,समाज को जोड़ने की बात कही है ,पर उस समय जब हमे अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए थी। गाँधी जी उस काल के संत थे जहाँ एक वजह थी –आजादी की , पर मोदीजी के विचारो और कर्मो का माहात्म्य ,एक प्रधानमंत्री के रूप में और आज आजादी के ७५ साल बाद ,एक विचारणीय बिंदु हैं मार्टिन लूथर किंग ,नेल्सन मंडेला ने भी व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की थी, परन्त् वो मांग किसी सरकार के नियंत्रण के विरूद्ध था ,स्वतंत्र भारत की मांग थी। आज जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, वो स्वतंत्र भारत में हम भारतीयों के उम्मीदों ,आशाओं की बात उठाई जा रही है।कैसा हो हमारा देश किस दिशा में जायेगा और क्या दशा हम निर्धारित करते है,यह अधिकार हमें हमारे प्रधान मंत्री ने दिया हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

हालाँकि हमारी सरकार के सामने बड़ी चुनौती, बढ़ती जनसंख्या, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और जनसांख्यिकीय परिवर्तन है, जिनका समाधान किये बगैर हम विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यद्यपि इन चुनौतियों की जांच करने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, सिफारिशें देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके और स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बनाए रखकर भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता समय की मांग है।विकसित भारत के लिए सुदृढ़ और निष्पक्ष नीतियों में पारदर्शिता के साथ एक चुस्त शासन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हैं। प्रतिनिधियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी अपेक्षित है। सुशासन के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों, काम करने के लिए विश्वसनीय डेटा के साथ हर मुद्दों के व्यवस्थित विश्लेषण की आवश्यकता है। समर्पण और सहानुभूति के साथ मामले पर विचार करने के लिए अच्छी सामूहिक प्रतिबद्धिता भी आयवश्क है ।इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित भारत को आकार देने के लिए विचार और सुझाव देने के लिए वेब पेज को सभी के लिए सुलभ बनाया गया है

विपक्ष विरोध करता है कुछ मात्र विरोध करने के लिए ,अपने नाम को सार्थक करने के लिए तो कुछ सत्ता में आने के लिए ,जनता को गुमराह करने के लिए। पर अगर एक बार आपने इन चार स्तम्भों को अपनी बात कहने का मौका दे दिया और ,उनके अनुसार देश का भविष्य बनाने की क्रिया शुरू कर दी, तो भारत का विकास ,भारतीयों के ही अनुसार ,विरोधी पक्षों को देश सँभालने में मुश्किलें पैदा कर देगा, क्योकि जनता अब अधिकारों के प्रति सबल और प्रबल हो जाएगी। भारत का विकास, २०४७ तक का उद्घोष अपने आप में एक क्रांति है, जिसमे गरीब ,किसान ,महिला और युवा शामिल है– हर परिवार शामिल है।

संदर्भ सूची

- प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की –नवीनतम समाचार ,नवम्बर ३० ,2023
- https://innovateindia.mygov.in/vViksit Bharat@२०४७, 11 December, २०२३
- www.forbesindia.com › blog › technology Building Viksit Bharat: Preparing the workforce for Vision २०४७
- VIKSIT BHARAT @ 2047 Concept Note for Discussion with Universities …www.ugc.gov.in/pdfnews/9991673_Viksit-Bharat2047-Discussion-Note-BasePaper.pdf
- www.narendramodi.in › viksit-bharat-the-vision-of Viksit Bharat: The Vision of PM Modi - NarendraModi.in February 24, २०२Cinema Mode off
- Viksit Bharat Sankalp Yatra, Realizing the potential of 140 crore Indians, youtube.com 4 months ago

♦♦♦♦♦

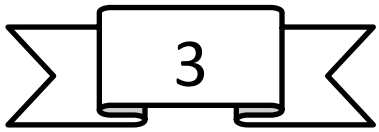

विकसित भारत का अर्थ

नविता कुमारी

जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविधालय

आज के दौर में विकसित भारत का स्वप्न हर एक भारतीय का है प्राचीन समय से ही भारत एक विविधता वाला देश रहा है आजादी के बाद भारत के विविधता , सभ्यता व गरिमा को ध्यान में रखते हुए कई विकास के कदम उठाए गए हैं भारत हमेशा से ही एक विकसित भारत का स्वप्न देखता आ रहा है स्वतंत्रता के पश्चात देश के कई आर्थिक परिवर्तन आए हैं लेकिन विकसित भारत का स्वप्न अभी भी अधूरा था इसी स्वप्न को पूरा करने तथा सभी देशवासियों के सर्वगीण विकास के लिए विकसित भारत विजन 2047 की शुरुआत की गई।भारत सरकार द्वारा अपने अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विकसित भारत के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को बताया।

विकसित भारत के द्वारा ही हर भारतीय का स्वप्न पूरा होते हुए नजर आ रहा है विकसित भारत का मतलब है ऐसा भारत जहां महिलाएं, बच्चे सुरक्षित हो, गरीब व निरक्षरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। कोई भी व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग महसूस ना करें।भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों पर हो और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसकी क्षमता पर गर्व किया जाए। भारत के हर व्यक्ति को उसका हक मिले।एक आर्थिक रूप से बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हर एक भारतीय का भी विकास हों वह भी विकसित हों ,ऐसा भारत ही सही मायने में विकसित भारत होगा 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा विकसित भारत @2047ः वॉइस फॉर युथ जारी किया उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्र विकसित तभी होता है जब वहां के व्यक्ति का विकास होता है पीएम ने आईडियाज फ्रॉम यूथ फॉर विकसित भारत 2047 की शुरुआत की।

कृषि, शिक्षा ,स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना व संचार तकनीक,महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता इलेक्ट्रॉनिक पावर में इन क्षेत्रों पर विकसित भारत बनने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है यह सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं इसलिए इन क्षेत्र के मध्य तालमेल

होना आवश्यक है। यह देश के विकास आर्थिक, सामाजिक व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के साथ हमेशा सकारात्मक विचार होना चाहिए,कि हम अपने देश को नवाचार व नए अविष्कार द्वारा देश में बदलाव ला सके।शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कह लो या मुद्दा, जिस दिन पूरा देश साक्षर हो जाएगा, उसी दिन हम विकसित भारत बनने से बस एक पग की दूरी पर होंगे।भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष, 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का स्वप्न है।भारत को विकसित बनाने में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति,सुशासन, पर्यावरणीय स्थितता, सरकार विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को सशक्त और उनकी समताओं में सुधार करके प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्तिकरण करके सर्वगीण विकास की दिशा में बढ़ रही है। विकसित भारत के विषय में सशक्त भारतीय नवाचार विज्ञान प्रौद्योगिकी संपन्न एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था सुरक्षा एवं सुशासन,विश्व में भारत की सर्वोच्चता शामिल है

विकसित भारत का उद्देश्य जिसमें प्रमुख है, देश के हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने के योग्य बनाना है इसमें आर्थिक विकास,निवेश और अलग–अलग उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा के लिए नीतियां लागू करना शामिल है। रोजगार व व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। इसी दृ ष्टिकोण में अन्य महत्वपूर्ण घटक है सतत विकास और सभी के जीवन में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे का विकास इसके लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं लागू की गई है जिसमें ट्रेनों ,विश्व स्तरीय सड़कें बंदरगाहों का निर्माण और डिजिटल कनेक्शन आदि शामिल है इससे निवेश उत्पादकता बढ़ाना ,आर्थिक समता का विस्तार और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आर्थिक विकास से सभी को लाभ प्राप्ति के लिए सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास को प्रमुखता देना है जो सरकार के शासन प्रशासन से वंचित है किनारे पर समुदाय को सशक्त बनाना। शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा के कई पहल शुरू की गई है जैसे,आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर्यावरणीय स्थिति भी विकसित भारत के लक्ष्य का हिस्सा है , इसमें भारत को स्वच्छ व हरा भरा करना है। विकसित भारत के प्रमुख स्तंभों में शासन में पारदर्शिता व दक्षता शामिल है इसके लिए कई प्लेटफार्म का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है कई प्लेटफार्म और जारी किए गए हैं। एक डिजिटल सशक्तिकरण की ओर भारत अपने कदम को बढ़ा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा उन कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की है जो विभिन्न योजनाओं नीतियों के तहत लाभार्थी के पात्र हैं परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचा है सरकार की योजनाओं के

बारे में प्रसार और लोगों तक जागरूकता पैदा करना। शिक्षा में सुधार व शिक्षा का प्रसार होना अति आवश्यक है विकसित देश बनने के लिए।

नए भारत विजन 2047 एक विकसित समृद्ध भारत है जो प्रकृति, आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं सभी क्षेत्र के सभी व्यक्ति को उनकी क्षमता के विकास में उन तक पहुंचाने के अवसरों के सादृश्य है विकसित भारत की संकल्प यात्रा एक जीवंत आशा का कारवा है यह हर भारतियों के घरों को सशक्तिकरण व उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है।

स्वतंत्रता के बाद से आज के दौर तक भारत एक विकासशील देश रहा है, जो विकसित बनने के पथ पर है भारत ने अपने को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बनाया है लेकिन, यह एक विकसित होने के लिए काफी नहीं है अतः भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत विजन 2047 लागू किया गया ।जिसके अनुसार भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष 2047, में एक विकसित राष्ट्र बनेगा।भारत अपने देश के हर क्षेत्र में सुधार व विकास कर रहा है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान,नवाचार का क्षेत्र हो। आज पूरा विश्व भी भारत की प्रशंसा करता है।भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। यहां की सभ्यता,विविधता व विचार जैसे वसुदेव कुटुंबकम इसे सबसे प्रमुख व अलग बनाता है।

संदर्भ सूची

- https://cleartax.in/s/viksit-bharat-2047
- https://www.narendramodi.in/viksit-bharat-the-vision-of-pm-modi-579810

♦♦♦♦♦

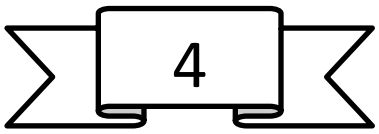

विकसित भारत @२०४७: एक अध्ययन

हिताक्षी गिल

जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

विकसित भारत का उद्देश्य है की भारत २०४७ तक एक समृद्ध और समाजवादी देश बने । यह एक दृष्टिकोण है जो सभी नागरिकों को समृद्ध समानता के अवसर प्रदान करता है। इसके तहत हमारा लक्ष्य है की भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों को बढ़ाना है ।

"जाति धर्म का भाव नहीं

विकसित अर्थव्यवस्था का आधार होगा

२०४७ में सुरक्षित और आत्मनिर्भर

भारत का सपना साकार होगा ''

विकसित भारत क्या है और इसका अर्थ ?

विकसित भारत 2047 एक दृष्टिकोण है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत 2047 तक एक समृद्ध, समाजवादी, और स्वावलंबी राष्ट्र बने। इस दृष्टिकोण के साथ भारत को सभी क्षेत्रों में विकास करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया जाता है।

जैसे आर्थिक, सामाजिक, और तकनीकी क्षेत्रों में। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, समाज को न्याय, समानता, और विकास के समर्थन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना ताकि वे समृद्ध और समृद्ध जीवन जी सकें। विकसित भारत 2047 भारतीय समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्य–निर्दिष्ट दृष्टिकोण है।

विकसित भारत 2047, 2047 में अपनी 100वीं स्वतंत्रता तक काउंटी को एक विकसित इकाई में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

विकसित भारत के चार स्तंभ हैं दृ युवा , गरीब , महिला और किसान ।

विकसित भारत का उद्देश्य और महत्व

विकसित भारत का दृष्टिकोण एक समृद्ध भारत है। जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रकृति के साथ स्थापित करता है और सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को उनकी क्षमता तक पहुंचने का अवसर देता है। और नागरारिको को आगे बड़ता है

वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट 2024 भाषण में कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास और विकास–सक्षम सुधारों की आवश्यकता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को उनके मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50–वर्षीय ब्याज–मुक्त के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। एमएसएमई को बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने में मदद करना भी विकसित भारत रोडमैप का एक हिस्सा होगा।

पीएम ने अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए भारत के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया. इसके बाद, सरकार ने पांच अलग–अलग विषयों पर सुझाव देने के लिए विकसित भारत से संबंधित श्आइडियाज पोर्टलश लॉन्च किया।

आर्थिक विकास–सामाजिक न्याय

विकसित भारत@2047 का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्वावलंबी बनाना है। इसमें नए उद्योग, नवाचार, और व्यापारिक संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य सम्मिलित हैं ।विकसित भारत में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें गरीबी को कम किया जाएगा और सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे।

शिक्षा और तकनीकि उन्नति और आत्मनिर्भर भारत

विकसित भारत@2047 में सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास है। शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार लागू किए जाएंगे।

विकसित भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है, जहां स्वदेशी उत्पादन, विकास, और नवाचार से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। और नागरिकों को रोजगार मिल सके ताकि देश के आर्थिक स्थिति ओर अच्छी हो सके।

पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्ट्राचार का अंत

विकसित भारत में पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण माना है, जहां प्रदूषण को कम किया जाए। ताकि नागरारीको का स्वस्थ मजबूत हो सके। साथ ही साथ पशू दृ पक्षी, जीव जंतु का भी ध्यान रखा जाएगा।

भ्रष्ट्राचार उन मुख्य कारण में से एक है जो भारत को विकसित होने से रोक रहा है। भ्रष्ट्राचार से लोग ओर गरीब होते जा रहे है। और अमीर ओर अमीर होते जा रहे है। इसे रोकने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की बहुत जरूरत है।

हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे भ्रष्ट्राचार को कम करने में सुधार हुआ है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की अगर हम इतिहास देखे तो हम देख सकते है के उनके साथ कितना भेद भाव हुआ है। परंतु अब काफी बदलाव आ चुका है । महिला घरों से भर निकल के अब अलग अलग काम शुरू करे रही है। सरकार ने भी काफी योजना बनाई है महिलाओं को आगे लाने के लिए जिसे महिलाएं आगे बड़े करे अपने आप को और भेतर बना चुके।

" खुशियां चारो तरफ छाई है।

देखो सोने के चिड़िया वाला देश में

सालो बाद सोने वाली लहर आई है । ''

२०४७ विकसित भारत का लक्ष्य हमारे देश को समृद्ध, समाजवादी, और स्वावलंबी बनाना है। अब तक कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, और आर्थिक विकास। हमने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की है और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सुधार किया ह। भारत में सामाजिक समानता और न्याय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति का विकास हो सके। इसके अलावा, हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की हैं और अधिक सुरक्षित और

स्वच्छ भारत के लिए प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत २०४७ तक हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे देश को समर्थन, सहयोग, और सामर्थ्य देने के लिए हम सभी का सामर्थ्य एकजुट करना होगा।

विकसित भारत २०४७[६] हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो हमें समृद्ध, समाजवादी, और स्वावलंबी भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय समाज को सभी क्षेत्रों में विकास करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हमें न्याय, समानता, और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति देश के विकास में सहभागी बन सके। विकसित भारत २०४७ एक सपना है जो हमें समृद्ध, उन्नत, और समाजवादी भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। यह सपना हमें एक सकारात्मक और समर्थ भविष्य की दिशा में ले जाने के लिए सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है।

संदर्भ सूची

- डेक्कन हरलैंड: विकसित भारत के लक्ष्य
- इन्नोएटिव इंडिया रू विकसित भारत /२०४७ का विजन और उसके विषय पर चर्चा
- राज भवन हरियाणा रू विकसित भारत /२०४७ के लक्ष्य को सरकार करने में लोगो का योगदान
- रिसर्च गेट – विक्सेत भारत का उद्देश्य और महत्व

♦♦♦♦♦

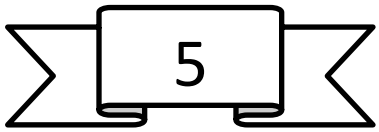

विकसित भारत @2047– सर्वांगीण विकास

डॉ. जूही सिंह

सहायक प्रोफेसर, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. बबीता वर्मा

सह आचार्य, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य, जिसे विकसित भारत 2047 के नाम से जाना जाता है, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिस वर्ष यह अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह दृष्टिकोण भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, प्रत्येक नागरिक को पाइप से पानी और पक्का आवास प्रदान करने, किसानों को ड्रोन से लैस करने, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उचित मूल्य वाली दवाओं की आपूर्ति का विस्तार करने और हरित और टिकाऊ आर्थिक नीतियों को लागू करने का आह्वान करता है। इसके अलावा, विकसित भारत 2047 अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने, भारत की भू–राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और उपनिवेशवाद की विरासत को दूर करने का प्रयास करता है। विकसित भारत 2047 महज एक तकियाकलाम से कहीं अधिक हैय यह एक संकल्प है, जो भारतीयों, विशेषकर युवा पीढ़ी को जोड़ता है जो अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। प्रधान मंत्री मोदी के इस विजन को ध्यान मं रखते हुए, ये लेख उन चुनौतियों की चर्चा करेगा जिन्हे आज हमारा देश संभावनाओं में परिवर्तित करने में सक्षम है।

परिचय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में, इतिहास एक समय अवधि प्रदान करता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत के लिए, ष्यह अमृत काल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने आस–पास के कई देशों का उदाहरण दिया जिन्होंने एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई और

विकसित राष्ट्र बन गए। "भारत के लिए, यह समय है, सही समय है", उन्होंने कहा कि इस अमृत काल के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाना चाहिए।

- इस परियोजना के परिणामस्वरूप भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता, सामाजिक कल्याण और मानव विकास के लिए एक रोल मॉडल और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थक बनना है। 18 से 20 अमेरिकी डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति आय, मजबूत राज्य वित्त और एक संपन्न वित्तीय क्षेत्र के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी तक पहुंचना।
- ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों में शीर्ष स्तरीय सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- नागरिकों के जीवन में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को हटाना और डिजिटल प्रशासन और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना।
- स्थानीय उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देना, विलय या पुनर्गठन करना और प्रत्येक क्षेत्र में तीन से चार वैश्विक चौंपियन तैयार करना। दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत करना और अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हरित विकास और जलवायु कार्रवाई का बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना। रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाने के लिए युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करना। दुनिया भर के शीर्ष 100 में कम से कम 10 भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और देश की शीर्ष 10 प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए विदेशी अनुसंधान एवं विकास समूहों के साथ सहयोग करना। विकसित भारत के चार स्तंभ हैं युवा, गरीब, महिला और किसान।
- विकसित भारत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की कल्पना करता है, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- विकसित भारत के 5 विषय हैं, जो इस प्रकार हैं–
- सशक्त भारतीय (स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी शक्ति, खेल, संस्कृति, देखभाल करने वाला समाज)
- संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था (उद्योग, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचा, सेवाएं, हरित अर्थव्यवस्था, शहर)
- नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप, डिजिटल)
- सुशासन एवं सुरक्षा

विश्व में भारत

- नये भारत का विजन एक समृद्ध भारत का है जो आधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रकृति और सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों के लिए उनकी क्षमता तक पहुंचने के अवसरों के अनुरूप है।

विकसित भारत 2047 – चुनौतियाँ और संभावनाएँ

- सर्वांगीण विकास की इस दृष्टि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भारत की जनसंख्या। नवीनतमसंयुक्त राष्ट्र डेटा के वर्ल्डोमीटर विस्तार के आधार पर, 5 मार्च, 2024 तक भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,437,482,776 है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.76ः के बराबर है। ख्2, आज भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है लेकिन अगर साकारात्मक दृष्टि से देखें तब यह समझ में आएगा कि यहीं जनसंख्या हमारे लिए एक वरदान है क्योंकि भारत की पास युवा शक्ति का एक मजबूत आधार है और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता हैप् हालांकि ख्1.4 अरब लोगों का होना, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का दोहन एक महत्वपूर्ण चुनौती है,श्श डिजिटल भुगतान समाधान कंपनी ईजीपे के प्रबंध निदेशक राशिद अली कहते हैं, "भारत की बड़ी आबादी अपने विशाल उपभोक्ता आधार को दखते हुए व्यवसायों को पूंजी लगाने के कई अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण युवा आबादी कुल आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक है," श्री अली कहते हैं। बदले में, ष्हमने सक्रिय रूप से रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, खासकर ग्रामीण आबादी के लिएष्। उन्होंने आगे कहा, ष्प्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि ने जनसांख्यिकीय लाभांश पैदा किया है, जो आर्थिक विकास के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।
- दूसरी चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था हैप् षविकसित भारतष् को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं में जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ती जनसंख्या वृद्धि शामिल है। बुनियादी ढांचागत, नियामक और राजकोषीय मुद्दे भी मौजूद हैं। इसके अलावा, जीडीपी पर पारंपरिक जोर महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों और प्रगति के मानवीय और सामाजिक आयामों को नजरअंदाज करता है। लेकिन ये भी सच है कि भारत दुनिया भर में आए झटकों के बावजूद डटा रहा और पिछले साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। स्थिर विकास के साथ प्रभावी मुद्रास्फीति नियंत्रण ने आगामी वर्ष में अर्थव्यवस्था की

संभावनाओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।बुनियादी कारकों की समीक्षा के आधार पर भारत के विकास के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। विश्व बैंक, ओईसीडी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी प्रमुख वित्तीय एजेंसियों ने भारत के लिए मजबूत विकास दर का अनुमान लगाया है, जिसका मूल्य 6% से अधिक होगा।

- भारत की अर्थव्यवस्था कई कारणों से मजबूत है। मजबूत घरेलू मांग, विदेशी निवेश में वृद्धि और फलते–फूलते शेयर बाजार के कारण देश आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है। अक्टूबर 2023 में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 21 महीने के उच्चतम स्तर लगभग छह बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो विदेशी निवेशकों के विश्वास में वृद्धि का संकेत देता है।
- भारत के वित्तीय आँकड़े मजबूती और स्थिरता दर्शाते हैं। देश का विदेशी भंडार, जो अब कुल +620 बिलियन से अधिक है, 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रुपया अभी भी आम तौर पर स्थिर है. ये भंडार एक आवश्यक बीमा पॉलिसी के रूप में काम करते हैं, बाहरी झटकों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करते हैं और जरूरत के समय एक संकट निधि के रूप में कार्य करते हैं।ख्6, हालांकि नियोक्ता खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी चाहने वालों को कुछ उम्मीद है। आने वाले महीनों में, भारतीय निगम 3.9 मिलियन से अधिक नौकरियाँ जोड़ने का इरादा रखते हैं, ज्यादातर परिवहन और लॉजिस्टिक्स उद्योगों में। हालाँकि, भारत में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने की कठिनाई को लेकर गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जैसी बाहरी बाधाएँ, विशेषकर पश्चिम एशिया में, भारत की आर्थिक स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं। मुद्रास्फीति, आयात लागत और वस्तुओं के प्रवाह पर प्रभाव से आगामी वर्ष में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। भारत असाधारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ता का एक स्मारक है क्योंकि यह 2024 की अनिश्चितता को पार करने के लिए तैयार है। भारत ने एक अभूतपूर्व महामारी से अप्रत्याशित संघर्ष और आर्थिक मंदी तक सब कुछ झेलते हुए झटके को झेलने और विकास जारी रखने की अपनी क्षमता साबित की है। ठोस नींव के साथ, राष्ट्र निरंतर आर्थिक विकास और स्थिरता की उम्मीद करते हुए सतर्क आशावाद के साथ 2024 का इंतजार कर रहा है।

- किसी देश की प्रगति का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है।
- यह निश्चित है कि शिक्षा, किसी भी देश के विकास की आधारशिला, निश्चित रूप से इस प्रयास के लिए आवश्यक होगी। यह पता लगाने के लिए कि शिक्षा का प्रत्येक भाग 2047 तक एक जीवंत और सशक्त भारत के निर्माण में कैसे योगदान देता है, इसके सभी घटकों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या–समाधान और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए, विकसित भारत पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार कर रहा है। योग्यता–आधारित मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, और सभी स्कूलों के पास पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। यह दूरी को कम करने का प्रयास करता है क्योंकि लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या निवास स्थान जैसे कारकों के आधार पर शिक्षा तक पहुंच में अंतर को समाप्त करने का समय आ गया है। वंचित आबादी के लिए केंद्रित पहलों में निवेश करें, जैसे आवासीय छात्रावास, ब्रिजिंग कक्षाएं और छात्रवृत्ति।
- विकसित भारत उद्योग की मांगों और विकासशील प्रौद्योगिकी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण का समन्वय करके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, माइक्रो–क्रेडेंशियल्स और व्यावसायिक अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से चल रहे कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहता है। राष्ट्र को उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो करियर बदलना चाहते हैं या बदलते रोजगार बाजारों के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण के आर्थिक विस्तार का समर्थन करने के लिए एक सक्षम कार्यबल आवश्यक है। इसके लिए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो व्यावसायिक मांगों के अनुरूप हों। ये पाठ्यक्रम आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, उचित मूल्य वाले होने चाहिए और इनमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों निर्देश शामिल होने चाहिए।
- पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में, विकसित भारत भारत को स्वच्छ और हरा–भरा बनाना चाहता है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहल शुरू की है। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सतत विकास विचारों का समर्थन किया है। सरकार संरक्षण प्रयासों, जलवायु–लचीले बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करती है क्योंकि वह पर्यावरणीय मुद्दों को कम करना चाहती है और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य प्रदान करना चाहती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, भारत

को उम्मीद है कि 2030 तक उसकी स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता का लगभग 50ः गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगा।

- नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में श्वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडाश पर दो दिवसीय जी20 नीति कार्यशाला का समापन किया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत के विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप, दुनिया भर में हरित और टिकाऊ विकास प्राप्त करने की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करना था।कार्यशाला के दौरान, जी20 शेरपा, अमिताभ कांत ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने और जलवायु कार्रवाई करने के लिए लगभग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के निवेश से लगभग 90 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार के अवसर पैदा होंगे। श्री अमिताभ कांत ने बताया कि वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जो कुल मिलाकर लगभग 350 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें 150 ट्रिलियन डॉलर संस्थागत फंड के साथ जुड़े हुए हैं।
- शासन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पीएम मोदी के विकसित भारत के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। सरकार ने सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों के वितरण को सुव्यवस्थित किया है, रिसाव को कम किया है, और यह सुनिश्चित किया है कि सहायता सीधे आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से इच्छित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। टीडीबीटी के उपयोग से, सरकार पैसे के रिसाव को रोकने और दस करोड़ फर्जी प्रविष्टियों को हटाने में सक्षम थी। डीबीटी की वजह से देश में करीब–करीब 3 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से रोका गया है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी को नियोजित किया है, जो व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाओं तक सहज और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करता है। अंततः, सामाजिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार का ध्यान समान विकास और सशक्तिकरण के प्रति उसके समर्पण को उजागर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक छोटी क्षेत्रीय शक्ति से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय प्रभावशाली रहा है। जी20 में इसकी सक्रिय भागीदारी, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आर्थिक ताकत का उपयोग करके अपनी नरम शक्ति

को पेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है, इस परिवर्तन को नाटकीय रूप से उजागर करती है। G20 में भाग लेकर, भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लागू करने सहित वैश्विक पहलों के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित कर सकता है। अपने सॉफ्ट पावर टूलबॉक्स में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में, ळ20 में भारत की भागीदारी इसकी स्थिति में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आकार देने और आपसी सम्मान और साझा मूल्यों के आधार पर गठबंधन बनाने में मदद करती है। जी20 ढांचे में भारत की सॉफ्ट पावर का यह प्रवेश देश के वैश्विक प्रभाव में एक नए अध्याय का प्रतीक है, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक परोपकार को आर्थिक कूटनीति के साथ मिलाकर भारत की वैश्विक भागीदारी में एक निर्बाध नया अध्याय बनाया गया है। भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख उदाहरण वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम है, जो COVID–19 महामारी के मद्देनजर प्रमुखता से उभरा। भारत ने वैश्विक फार्मास्युटिकल पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए, 90 से अधिक देशों को लाखों वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करके स्वास्थ्य सुरक्षा और सहयोग क प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वैश्विक संकट के समय में वैक्सीन कूटनीति के इस कार्य ने जी20 और उसके बाहर वैश्विक स्वास्थ्य में भारत के नेतृत्व को उजागर किया और पूरे विश्व समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित एक भरोसेमंद और जिम्मेदार भागीदार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। जैसा कि डॉ. एस. जयशंकर ने ठीक ही कहा है

- विकसित भारत अगले 25 वर्षों के लिए एक दृष्टिकोण और लक्ष्य दोनों है।ख10,
- पिछले पांच वर्षों में वैश्विक परिदृश्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, भारत अपने संसाधनों के आश्वासन के साथ इसे नेविगेट करने के लिए तैयार है।
- निस्संदेह, वैश्वीकरण हो रहा है, लेकिन घरेलू उद्यमों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के साथ–साथ खुलेपन की भी आवश्यकता है। आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन, विकास और देश की धारणा को आकार देने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आवश्यक सुधारों के साथ–साथ उन सुधारों को भी लागू कर रहा है जो उसे करने चाहिए। यह प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का सामंजस्य बिठाने में सक्षम है। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता शांतिपूर्ण ढंग से सह–अस्तित्व में रह सकते हैं।

निष्कर्ष

- प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य से प्रेरित होकर, भारत सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हासिल कर रहा है। भारत स्पष्ट रूप से विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश था और अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाओं जैसी पहलों के कारण बढ़ता सांस्कृतिक पुनरुत्थान इस बात की गारंटी देता है कि भारतीय संस्कृति ने वैश्विक मान्यता हासिल कर ली है।
- विकसित भारत के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण की नींव भारत की पूर्ण क्षमता का एहसास करने और देश को विकास और धन के पहले अनसुने स्तर तक ले जाने की एक साहसी और क्रांतिकारी रणनीति है। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अधिक समावेशी और लचीला हो, जहां जनभागीदारी देश की सफलता की आधारशिला के रूप में कार्य करे। प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता देता है।

संदर्भ सूची

- https://pib-gov-in/PressReleaseIframePage-aspÛ\PRID¾1985077
- https://www-worldometers-info/world&population/india&population
- https://www-thenationalnew com/business/economy/2023/01/16/why&indias&growing&population&is&an&asset&to &its&economy/#:~:teÛt¾%E2%80%9CIndia's%20large%20population%20provides%20 many] especially%20for%20the%20rural%20population]
- India's GDP eÛpected to grow at 6-8% in FY25] to attain upper middle&income status by 2031] Mar 06] 2024] https://economictimes-indiatimes-com/news/economy/indicators/india&to&grow&at&6&8&in&fy25&to&become&upper &middle&income&country&by&2031/articleshow/108260501-cms\from¾mdr
- https://www-firstpost-com/opinion/vantage&what&does&2024&have&in&store&for&indias&economy&1357 0252-html
- RBI MPC: India's foreÛ reserves at $622-5 bn as of February 2] says Governor Shaktikanta Das] Feb 09] 2024] https://economictimes-indiatimes-com/news/economy/indicators/rbi&mpc&indias&foreÛ&reserves&at&622&5&bn&as& of&february&2&says&governor&shaktikanta&das/articleshow/107512718-cms\from¾mdr
- https://www-narendramodi-in/viksit&bharat&the&vision&of&pm&modi&579810
- NITI Aayog Aims To Achieve Viksit Bharat By 2047 Through Green And Sustainable Growth] July 30] 2023] https://swachhindia-ndtv-com/niti&aayog&aims&to&achieve&viksit&bharat&by&2047&through&green&and&s ustainable&growth&80370/
- https://www-linkedin-com/pulse/g20&indias&soft&power&new&era&global&influence&santosh&g&qnoac\tr k¾article&ssr&frontend&pulse_more&articles_related&content&card
- https://twitter-com/DrSJaishankar/status/1733538869633540168

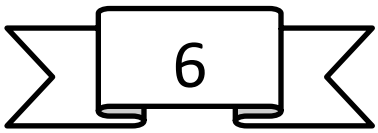

भारत की दिशा–निर्देशः 2047 में एक उदार व विकसित राष्ट्र

उषा बाल्मीकि

पीएच.डी. छात्र, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, भुवनेश्वर

"चल तू पग– पग में, बाढ़ तू नभ–नभ में, ए मेरे भारत तू , बढ़ हर घर– घर में"

भारत को विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश बनाने का लक्ष्य विकसित भारत 2047 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसको पूरा करने ही हमारा उद्देश्य है, विकसित भारत का स्वरूप एक संकल्प है, एक अटल विश्वास है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व के सम्मुख पुनः एक नई पहचान नया अस्तित्व प्रदान कर उसकी गरिमा विश्व गुरु के रूप में सदैव के लिए पुनः प्रतिस्थापित करना है। विकसित भारत का विजन भारत को सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई पर पहुंचने का है ताकि भारत अपने आप को फिर से जान सके भारतवासी अपने खोई हुई ज्ञान संपदा को फिर से जान सके और उसे आत्मसात हो सके। विकसित भारत 2047 का उद्देश्य भारत को पुनः उसके संस्कृत आवश्यकता के महत्व को उजागर कर उसको स्थापित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में हर एक भारतीय का योगदान अद्भुत और अविश्वसनीय है।

संभावनाएं एवं चुनौतियां भावी जीवन की लक्ष्य होती है। संभावनाएं हमें आशा देती है तो, चुनौतियां हमें संघर्ष से लड़ने हेतु ताकत। जीवन में संभावनाएं एवं चुनौतियां इस प्रकार है जिस प्रकार पहाड़ों में बहता हुआ झरने का पानी और उसके मार्ग में आने वाले वीहड । विकसित और विकासशील एक ही पक्ष के दो पहलू हैं, तथापि एक दूसरे से भिन्न है, विकसित भारत विकसित का तात्पर्य पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति तो विकासशील का तात्पर्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्पर रहना ।वर्तमान समय में भारत एक विकासशील देश माना जाता है अर्थात हर क्षेत्र में भारत को विकसित देश बनाने का प्रयत्न जारी है विकसित भारत एक भावी लक्ष्य है जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को हर क्षेत्र से पूर्ण रूप से विकसित कर नए रूप से उजागर करना है ।

भारत सरकार के सहयोग से दिसंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत की परिकल्पना की अद्भुत पहल की गई है जिसे 2047 तक पूर्ण करने का भावी लक्ष्य तय किया गया

है। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का प्रयास सदियों से किया जा रहा है, हालांकि बहुत हद तक इन लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा चुका है अपितु इसके मार्ग में कुछ संभावनाएं एवं चुनौतियां भी हैं।

विकसित भारत@2047 में संभावनाएं और चुनौतियाँ कई हो सकती हैं। इनमें वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समस्याएं शामिल हो सकती हैं। उच्च जनसंख्या, गरीबी, विकास के असमानता, पर्यावरणीय प्रदूषण, संगठनशील अपराध, टेक्नोलॉजी के विकास में असमंजस, और सामाजिक विविधता जैसी समस्याएं चुनौतियाँ प्रदान कर सकती हैं। इन सभी क्षेत्रों में नए सोच की आवश्यकता होगी और समाधानों के लिए सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक होगा।

- विकसित भारत@2047 के लिए कई संभावनाएं हो सकती हैं।
- सर्वांगीण समाज का निर्माण

"यह जहां है मेरा यह जहां है तेरा, कुछ नहीं विकसित भारत का स्वपन है मेरा"

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना से भारतीय सर्वांगीण समाज का निर्माण की संभावना है जैसा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा स्कूल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है जिससे बच्चों में नैतिक नैतिक मूल्य सहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, संवादात्मक, तार्किक समस्या समाधान, और मौलिक कर्तव्य के विकास पर जोर दिया गया है जिसका सफलता का प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज के विकास और निर्माण निर्माण पर पड़ता है। किसी भी देश की विकास की रन उसे देश की युवा पीढ़ी होती है, जब तक युवा पीढ़ी में सर्वांगीण विकास का गुण निहितार्थ नहीं होगा वह देश विकास के पद पर पीछे रहेगा, किंतु 2047 तक देश की युवा पीढ़ी को सर्वांगीण रूप से विकसित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

- शिक्षित भारतीय समाज

शिक्षा और ज्ञान के अभाव में विकास अपूर्ण है, पंगु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा 2047 से पहले तक भारतीय युवा वर्ग में नई पीढ़ी को बेसिक लिखने पढ़ने तार्किक चिंतन जोड़ घटाव भाग गुणा करने की कला का समावेशन का कार्य किया जा रहा है जिसमें हर वर्ग हर क्षत्र के लोग लाभान्वित होंगे साथ ही साथ युवा वर्ग में भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा कला साहित्य मातृभाषा के

प्रति सम्मान और संवेदना का सृजन किया जा रहा है जो विकसित भारत उन 2047 की संभावनाओं को पूरा करता है।

- भारतीय ज्ञान एवं परंपरा

जिस देश में अपने मात्रा पारंपरिक ज्ञान एवं भाषा की प्रति उदासीनता व्याप्त हो वह देश विकास के मार्ग पर वैसा ही प्रतीत होता है जैसे लहरों के बिना बाटी कश्ती किंतु पिछले कुछ दशकों से भारत सरकार द्वारा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारतीय ज्ञान परंपरा कला साहित्य एवं मातृभाषा की प्रति नई चेतना एवं संवेदनशीलता देखने को प्राप्त हुई है। भारतीय ज्ञान एवं परंपरा के प्रति प्रेम विकसित प्रेम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना की कल्पना को पूर्ण करता हुआ साबित हो रहा है।

- आर्थिक भारतीय समाज

भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास और समृद्धि की संभावना है, जो लोगों के जीवन में सुधार लाएगा। जी हां हम आर्थिक भारतीय समाज की बात कर रहे हैं केवल आर्थिक समाज की नहीं जैसा की प्राचीन काल से ही भारत कला संस्कृति एवं वाणिज्य वह व्यापार का केंद्र माना जाता रहा ह किंतु ब्रिटिश काल में भारतीय ज्ञान परंपरा सहित भारतीय कुटीर उद्योग का पतन एक नासूर साबित हुआ ।भारत अपनी भारत अपने भारतीय वाणिज्य–व्यापार की परंपरा और पहचान को खोता गया और पश्चिमीकरण के रंग में समाहित हो गया लेकिन पुनः भारतीय कुटीर उद्योग को समय के मांग के अनुसार तकनीकी पर आधारित वाणिज्य– व्यापार एवं हस्तकला को पुनः जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका जीवंत उदाहरण है जिसका उद्देश्य भारत की विश्व भारत को विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उजागर करना है।

- राजनीतिक एवं धार्मिक भारतीयकरण

इसके माध्यम से भारतीयों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति संवेदना का संचार किया जा रहा है, ताकि भारतीय प्रशासनिक ढांचा के ज्ञान से भली– भांति परिचित, हो और सही निर्णय निर्णय लेने हेतु सक्षम साथ ही साथ भारतीय धार्मिक नीतियों की प्रति तार्किक चिंतन और संवेदना का संचार किया जा रहा है ताकि भारत अपनी खोई हुई धार्मिक पहचान को प्राप्त कर सके और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना परिकल्पना पूर्ण हो सके।

- प्रौद्योगिकी और अभियान्त्रिकी में अग्रणी

उच्च प्रौद्योगिकी और अभियान्त्रिकी क्षेत्र में भारत की गरिमा बढ़ेगी और उसे ग्लोबल नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएगा। प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी विकसित भारत के स्वप्न के लक्ष्य को पूरा करने में एक प्रमुख घातक साबित हो रहा है।

- सामर्थ्यकोष और संगठनशीलता

सरकार और समाज में संगठनशीलता और व्यवस्था का विकास होगा, जिससे कि सभी सामाजिक वर्गों को विकास का लाभ मिले। सरकार और समाज में सामंजस स्थापित कर संगठन चलता को दिन करता है। सरकार और समाज में संगठन चलता और व्यवस्था का विकास होगा जिससे कि सभी सामाजिक वर्गों का विकास का लाभ मिले और विकसित भारत का मार्ग।

- पर्यावरण सुरक्षा

पर्यावरण ही हमारा जीवन है दिन प्रतिदिन पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं संवेदनशीलता भारत को पुनः खोई हुई प्रकृति और पर्यावरण प्रेम से रूबरू करवा रही है। पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाए जाएंगे, जो स्थायी और सामर्थ्यकोषील विकास की संभावनाओं को सुनिश्चित करेगा।

- सामाजिक और राजनीतिक सुधार

विकसित भारत के संकल्प के तहत समाज से दूषित तत्वों का विनाश कर समानता न्याय समावेशिता की भावना का संचार किया जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक विकास के माध्यम से समाज में न्याय, समानता, और विविधता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- साक्षरता और शिक्षा का प्रसार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा ड्रॉप आउट रेट रेट को कम करने और सबतक पहुंच सुनिश्चित कर सबकी समावेशन द्वारा साक्षरता और शिक्षा के स्तर में सुधार, खासकर गरीब और अति–गरीब वर्गों में, भारत को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा।

- चुनौतियाँ

जहां चाह होती है वहीं राह होती है पर साथ में कठिनाइयां भी होती हैं। विकसित भारत 2047 की राह भी कुछ चुनौतियों से परिपूर्ण है जिसके विकार बिना विकसित भारत 2047 की कल्पना संभव नहीं है। भारत की दिशा–निर्देशरू 2047 में एक उदार, विकसित राष्ट्र 2047 में भारत को

एक विश्वस्तरीय शक्ति के रूप में देखना संभव है, लेकिन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित हैं कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ जो हमें प्राप्त हो सकती हैं।

"बढ़ तू आगे चल तू आगे विकसित भारत की राह में अडिंग रहे आगे"

- भारतीयता की भावना के प्रति एकीकरण

भारत विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है यहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा ,संस्कृति के लोग आपसी सौहार्द्ध से जीवन यापन करते हैं अपितु समाज में कुछ अवांछित दूषित तत्व समाज की सौहार्द्रता को भंग करते हैं। अतः ऐसे दूषित तत्व भारत जैसे विभिन्नताओं में एकता की देश में एकल भारतीयता की भावना को मार्ग कर विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के मार्ग में चुनौती हैं।

- समय

विकसित भारत के स्वपन को 2047 तक पूरी करने की परिकल्पना समय रूपी बाध्यता तत्व से भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत जैसे विशाल भूखंड वाले देश में विकसित भारत के सपने को निश्चित समय तक पूरा करना भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है क्योंकि विकसित भारत का संकल्प केवल एक क्षेत्र वर्ग तब के यह जाति से नहीं बल्कि समग्र भारत के विकास से है कॉविड–19 जैसी माहवारी महामारी अगरपुनःअपने पैर पसारे तो इस लक्ष्य को 2047 तक प्राप्त करना चुनौती भरा साबित हो सकता है।

- सामाजिक असमानता

भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की भावना का विनाश कर सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित कर विश्वास प्राप्त करना भी एक विशाल पूर्ण विशाल चुनौती पूर्ण कार्य है। समाज में असमानता को कम करना और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

- जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में एक विशालकाय चुनौती के रूप में हमारे समक्ष खड़ी है। जिसका सामना कर उसे पर संतुलन पाना कठिन है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए

हमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के लिए नए तकनीकी उत्पाद और सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है।

- तकनीकी उन्नति

हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों की तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित कर पूर्ण डिजिटल भारत के सपनों को पूरा करना भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है। बढ़ती तकनीकी की वजह से इंसान श्रम की जगह मशीन ले रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है तकनीकी उन्नति और नवाचार के माध्यम से हमें उत्पादकता में वृद्धि करने और नए रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरूरत है।

- राजनीतिक स्थिरता

भारत जैसे विविधताओं वाले लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है। राष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता और संघर्षमुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संविधानिक नियंत्रण और सामाजिक समझ की मजबूती की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समस्याएं और चुनौतियां तो राह में आता ही रहती हैं लेकिन उन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही विकास होता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर भारतीय वाशी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उपयुक्त चुनौतियों का का सामना करते हुए उपयुक्त संभावनाओं को पूरा कर हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को अद्भुत अविश्वसनीय तरीके से पूरा कर सकते हैं। भारत को विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से सुदृढ़ देश बनाने का लक्ष्य विकसित भारत 2047 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसको पूरा करने ही हमारा उद्देश्य है। 2047 तक, हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास करने और सहयोग करने की आवश्यकता है। यह संभव हो सकेगा जब हम एकजुट होकर समस्याओं का सामना करें और समाधान ढूंढें। इस साथियों के सहयोग से ही हम सपने में देखा गया विकसित और उदार भारत का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ सूची

मेरी सरकार (2023) विजन विकसित भारत /2047 के लिए विचार

https://innovateindia-mygov-in/viksitbharat2047/

♦♦♦♦♦

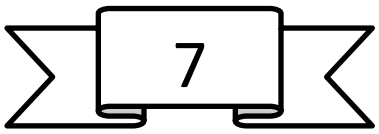

विकसित भारत के समक्ष चुनौतियाः बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में एक अध्ययन

चंद्रिका आर्य

पीएचडी शोधार्थी, राजनितिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्ष 2024 का अंतरिम बजट संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन किया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा की सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि देश के विकास की योजना सर्वव्यापी सर्वांगीण एवं समावेशी है। वर्तमान में सरकार नागरिकों की क्षमताओं में सुधार कर उन्हें सक्षम व सशक्त बनाने की ओर ध्यान दे रही है। विकसित भारत का अर्थ है कि वर्ष 2047 तक जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना हैद्य विकसित भारत से तात्पर्य है कि आधुनिक मूलभूत ढांचे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध भारत का निर्माण करना जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को अपनी क्षमताआं का पूर्ण रूप से विकास करने का अवसर प्रदान हो सके। सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार विकसित भारत के चार स्तंभ निर्धारित किए गए हैं –गरीब, युवा, महिला और किसान। विकसित भारत के विजन में इसके कुछ पहलू भी निर्धारित किए गए जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रगति एवं सुशासन शामिल है। देश में ऐसी अर्थव्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जा सके तथा सभी का उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित हो। उद्यमिता एवं प्रतिस्पर्धा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाकर 21वीं सदी की चुनौतियां का सामना किया जा सके। इसके साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए एक स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ पाने में सक्षम हो। विकसित भारत के अंतर्गत एक समावेशी समाज का निर्माण करने की संकल्पना भी शामिल है जो नागरिकों के कल्याण के साथ–साथ उन्हें एक गरिमामय जीवन प्रदान कर सके। जो समाज में न्याय को स्थापित कर सके तथा समानता के अधिकार को सुरक्षित कर सके। समाज के सभी

नागरिक भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखते हुए इसका जश्न मना सके। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक लक्षणों को हासिल करने के साथ–साथ इसमें दुरुस्त शासन प्रणाली का लक्ष्य भी रखा गया है। विकसित देश के लिए एकपारदर्शी व जवाबदेह शासन व्यवस्था का होनाआवश्यक है जो देश की स्थिति तथा नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सुदृढ़ नीतियों का निर्माण व क्रियांवन कर सके।

भारत में विकास की गति तेज होते हुए भी देश अनेकों समस्याओ से जूझ रहा है जैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या विकसित भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन उसे देश की जनसंख्या की रोजगार दर से लगाया जा सकता है। हालांकि नवीनतम डेटा आशा की एक किरण दिखाता है, क्योंकि भारत की बेरोजगारी दर में हाल ही में गिरावट आई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सर्वेक्षण (एनएसएसओ) के अनुसार , शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी–मार्च 2023 के दौरान घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 8.2 प्रतिशत थी। परंतु मार्च 2024 में जारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं। 'द इंडिया इंपलॉयमेंट रिपोर्ट 2024श के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2 फीसदी थी जो 2022 में बढ़कर 65.7 फीसदी हो गई।अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट (आईएचडी) ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है।

भारत में बेरोजगारी व प्रकार

बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें किसी रोजगार के लायक व्यक्ति को काम तलाश किए जाने के बाबजूद भी काम नहीं मिल पाता है। आजादी के बाद से ही भारतीय सरकारों द्वारा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए परंतु अथक प्रयासों के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या पिछले कुछ वर्षों से समाप्त होने की बजाय गंभीर रूप धारण कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार देख सकते हैं जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारीद्य यह विशेषतः कृषि या असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें एक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति बिना आवश्यकता के अपनी क्षमताओं से कम कार्य करते हैं। आम भाषा में इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता

है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को वर्ष के कुछ निश्चित मौसम में रोजगार की उपलब्धता नहीं होती है। बेरोजगारी का यह प्रकार भारत में अधिकतर पाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि क्षेत्र में लगे हुए मजदूर मौसमी बेरोजगारी का शिकार होते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ी है। यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम तथा श्रमिकों के कौशल के बीच संतुलन की एक स्थिति है। भारत के लोगों में प्रयुक्त कौशल के अभाव के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। यह स्थिति भारत के मूलभूत ढांचे जैसे शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में कमी होने से जन्म लेती है। शिक्षा का अभाव होने के कारण नागरिकों में कौशल का विकास नहीं हो पता है जिसके कारण वह नौकरी ले पाने में असफल होते हैं। पूरे विश्व में भारत युवाओं की सबस अधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण देश के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती है कि युवाओं का कौशल विकास किया जाए ताकि वह देश के लिए एक संसाधन बन देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। 21वीं शताब्दी में चौथी औद्योगिक क्रांति होने से नौकरियों की उपलब्धता पर जो प्रभाव पड़ा है उसको तकनीकी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। बेरोजगारी की इस श्रेणी से विश्व के सभी देशों को लगभग समान खतरा है परंतु विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के सामने यह एक गंभीर समस्या है। क्योंकि यह देश पहले से ही गरीबी व बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और प्रद्योयोगिकी में विकास जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से नौकरियों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। वर्ष 2016 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में ऑटोमेशन के प्रभाव से नौकरी जाने के खतरे का अनुपात वर्ष दर वर्ष 69ः है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रकार सुभेद्द बेरोजगारी भी है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रूप से कार्यरत है जिसके कारण उनका कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है और यह तबका किसी भी प्रकार की सरकारी कानून की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता और सरकारी पेंशन आदि का लाभ से भी वंचित रहता है। ऐसे कार्यरत लोगों को आमतौर पर बेरोजगार समझा जाता है क्योंकि उनके कार्य का कोई औपचारिक विवरण नहीं होता। भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, कौशल विकास का अभाव, शिक्षा प्रणाली में कमी, आर्थिक असमानताएं कृषि पर अधिक निर्भरता।

बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारे उठाए गए कदम

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 1979 में सरकार द्वारा ज्त्लैम्ड योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल से प्रशिक्षित करना था। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति

व महिलाओं को प्रशिक्षित करने में प्राथमिकता दी गई। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की बढ़ोतरी के लिए वर्ष 1980 में कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) का शुभारंभ किया। वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दो मौजूदा रोजगार कार्यक्रम पहले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को केंद्र व राज्य की 80रू20 के अनुपात की लागत के साझे प्रयास से पुनः लागू किया गया।

इसके अलावा वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति को प्रतिवर्ष 100 दिन सवेतन काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा भी विभिन्न समाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई जैसे कि रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किया गया जिसका उद्देश्य देश के युवाओं में एक सुरक्षित और बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग संबंध कौशल का विकास करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया योजना का ऐलान किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है जो युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सके।

बेरोजगारी से निपटने के उपाय

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसकी विशेषता एक महत्वपूर्ण युवा आबादी है, देश में बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने की अपार क्षमता रखता है। बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, कौशल विकास और रोजगार सृजन पहलों के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय लाभांश को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर, भारत अपने युवाओं को नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकता है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी और उद्योग सहयोग को प्रोत्साहित करने से युवा कार्यबल के कौशल और आकांक्षाओं के साथ संरेखित अधिक रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिल सकती है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाई गई नीतियां जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे इसके लिए नीति निर्माता को भारत में हो रहे जनसंख्या बदलाव और विकासात्मक नीतियों के साथ सही ढंग से तालमेल बैठाने की जरूरत है। अगर यह नीतियां युवाओं में कौशल विकास और उनको उद्यमिता की तरफ प्रेरित

करने में सफल हो जाती हैं तो यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगी। देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव का लाभ उठाने के लिए नीति निर्माता के लिए आवश्यक है कि वह देश के बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा स्वास्थ्य तथा काशल विकास में निवेश करें जिससे युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्हें मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सके। इस संदर्भ में शहरी नीति नियोजन के कार्य को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया जैसी नीतियों के क्रियान्वन के परिणाम स्वरुप आने वाले समय में भारत के कामकाजी युवाओं की बड़ी आबादी अपने राज्य की शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होगी। जिसके परिणाम स्वरुप शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि देखने को मिल सकती है ऐसे समय पर पलायन करने वाली लोगों को शहरी बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र सामाजिक सुरक्षा आदि का लाभ कैसे पहुंचाया जाए इस पर शहरी प्रशासन को तत्काल रूप से मंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए मोदी सरकार द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं को प्रभावी एवं सावधानी से लागू करने की आवश्यकता है।

♦♦♦♦♦

डी सी आर सी

विकासशील राज्य शोध केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281